से यही आग्रह है कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे, नहीं तो जून महीने में स्थिति इतनी भयावह हो जायेगी कि मवेशी भी पानी के अभाव में मरने लगेंगे और मनुष्यों की हालत भी बहुत खराब हो जायेगी। इधर सरकार का जल्दी ध्यान जाना चाहिये। धन्यवाद।

Drinking Water problem in Rajasthan

डा. अबरार अहमद खान (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान में पीने के पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के लिये यह कहना कि वहां पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है या यह कहना कि वहां पशु पीने के पानी के अभाव में मरने लगे हैं या यह कहना कि वहां से लोग अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थानों पर पलायन करने लगे हैं तो कोई खास बात नहीं होगी। अभी दो दिन पहले मैं राजस्थान में सबसे ज्यादा चलने वाला न्यूजपेपर "राजस्थान पत्रिका" पढ़ रहा था। जब मैंने उसमें पीने के पानी की समस्या के बारे में पढ़ा तो मेरे रौंगटे खड़े हो गये क्योंकि उसमें लिखा था कि पेयजल की किल्लत से गांवों में जेवर बिक रहे हैं और उसमें लिखा था कि पेयजल की समस्या के कारण वहां स्त्रियों की अस्मत के सौदे हो रहे हैं।

महोदय, गत दो माह पूर्व मैंने इसी माननीय सदन में विशेष उल्लेख किया था और उसमें कहा था कि पहले से ही उन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाय, जिन गांवों में जहां रेलों से या बैलगाड़ियों से या टैंकरों से पानी पहुंचा सकते हों, वहां पहुंचाने की अभी से व्यवस्था की जाय। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वहां पीने के पानी के लिये जेवरों को बेचा जा रहा है, पीने के पानी के लिये वहां स्त्रियों की अस्मत के सौदे हो रहे हैं, जो वास्तव में एक रौंगटे खड़े कर देने वाली बात है।

महोदय, सन 1987 में भी इस देश के अन्दर अकाल पड़ा था और इससे कहीं भंयकर अकाल पड़ा था, इससे कहीं ज्यादा भंयकर पीने के पानी की उस समय समस्या थी। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी राजस्थान गये, वहां गांव-गांव में जाकर देखा और 900 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया। वहां रेलों से, टैंकरों से, बैलगाड़ियों से, जैसे भी जहां-जहां पानी जा सकता था, दिया। अब राजस्थान की जनता ने इस जनता दल की सरकार को पच्चीस की पच्चीस सीटें दी हैं और मुझे यह कहते हुये दुख हो रहा है कि आज वहां पानी की खातिर स्त्रियों की अस्मत के सौदे हो रहे हैं, वहां की स्त्रियों के जेवर बिक रहे हैं, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां मवेशी मर रहे हैं, लेकिन इस सरकार से कोई वहां जाने वाला नहीं है, कोई वहां जाकर उनके पीने के पानी की समस्या पूछने वाला नहीं है।

महोदय, केन्द्र सरकार ने 124 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया पांच वर्ष के आवर्ती कोष के लिये। उस पर भी वहां के चीफ मिनिस्टर कुंडली मारकर बैठे हुये हैं। राजस्थान में जो 15 अप्रैल से रोजगार देने के काम चालू हो जाने चाहिये थे, वे सभी अभी चालू नहीं हुये हैं क्योंकि उसके लिये 24 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को देना है और 91 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार को देना है, लेकिन राज्य सरकार वह पैसा भी नहीं देना चाहती है। जो पानी की सुविधा के लिये या रोजगार के लिये कार्य वहां चलने चाहियें वे आज तक नहीं चल पाये हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस केन्द्रीय सरकार के कान खोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वह राजस्थान, जिसने आप को पच्चीस की पच्चीस सीटें दीं, आज वह राजस्थान बिलख रहा है, वहां पानी के लिये स्त्रियों की अस्मत के सौदे हो

[डा० अबरार अहमद खान]

रहे हैं, उनके जेवर बिक रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, कम से कम उनके लिये केन्द्रीय सहायता देकर पीने के पानी की व्यवस्था तो आप करायें, जिससे जून महीने में वे अपना जीवन तो बचा सकें। अगर इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो शायद इस जून के महीने में कई लोग पानी के अभाव में मर जायेंगे, हजारों मवेशी मर जायेंगे और खास तौर से जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मैं सवाई माधोपुर से ताल्लुक रखता हूं, वहां एक टाइगर-प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपया उस पर हमारी सरकार ने खर्च कर रखा है लेकिन, वहां भी पीने के पानी की कमी है, मैं तो अपनी आंखों से देखकर आया हूं, अगर वहां भी पानी की व्यवस्था न की गई तो वह बेजुबां जानवर ऐसे हो जायेंगे, जैसे कुछ कह नहीं सकेंगे और उन्हें जाकर कोई देख नहीं सकेगा यानी वह जंगल श्मशान घाट बन जायेगा। इसलिये कम से कम आदमियों के लिये, जानवरों के लिये, मवेशियों के लिये पानी की व्यवस्था तो सरकार को करानी चाहिये। मेरा आप के माध्यम से इतना ही आग्रह है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Honourable Members, it is already 2. 15. The Deputy Chairman has suggested that there may be a lunch interval till 2. 30. But to be fair to lunch at least half an hour should be given. So the House stands adjourned for lunch to meet again at 2. 45.

The House then adjourned at fifteen minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-eight minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Shri M. A. Baby) in the Chair.

GOLD (CONTROL) REPEAL BILL 1990—Contd.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण नियंत्रण निरसन वापसी यानी रिपील विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन खैर, देर आए, दुरुस्त आए। यह एक विशेष समय की मांग थी। उस समय यह कानून बना था, युद्ध की समस्या थी और अनेक समस्यायें थीं और उस समय इस विधेयक को, इस कानून को लाना आवश्यक था, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि बहुत सी बातें माननीय सदस्य इस विषय में कह चुके हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से दो-चार बातें जरूर कहना चाहती हूं।

आज इस देश में लाइसेंस वाले स्वर्णकारों की संख्या, पिछले दो साल की लेटेस्ट फिगर्स ही मैं आपको बतलाऊंगी कि 1988 में 15,713 थी और 1989 में में 16,704 थी। इसी प्रकार जो सार्टि-फिकेट प्राप्त स्वर्णकार हैं उनकी संख्या 1988 में 3,62,307 के करीब थी और 1989 में 3,75,789 के करीब थी। लेकिन इसके अलावा भी छोटे-छोटे कस्बों में और छोटी-छोटी जगहों में बहुत से स्वर्णकार हैं जिनके पास न कोई लाइसेंस है, न सार्टिफिकेट है लेकिन फिर भी वह काम करते हैं। उपासभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में स्वर्णकार, स्वर्ण आभूषण के कारीगरों की जो यह संख्या है वह क्या इशारा करती है? क्या इंगित करती है? स्वर्ण आभूषण की इस देश में बहुत बड़ी मांग है और सिर्फ इस देश में मांग नहीं बल्कि इसको काफी बड़ी मांग विदेशों में भी है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि जब विदेशों में भी इसकी मांग है तो इसके निर्यात के द्वारा हम बहुत बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं और इसलिए यह सही है कि पिछली सरकार ने भी बहुत से इंसेंटिव्ज दिये थे, खासकर के गोल्ड ओर्नामेंट्स के एक्सपोर्ट के लिए।